

उत्तराखण्ड शासन  
लघु सिंचाई विभाग,

संख्या 493 / ।।—2008–03(02) / 2008,  
देहरादून, दिनांक 25 अप्रैल, 2008

शुद्धिपत्र

शासनादेश सं 441 / ।।—2008–03(02) / 2008 दिनांक 21.04.2008 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदो में ₹ 0 491.82 लाख (लगभग चार करोड़ इक्षणवें लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि रामस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड के निर्दर्शन पर रखी गयी थी। उक्त शासनादेश के अन्तिम प्रस्तर में त्रुटिवश “इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीषकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें ढाला जायेगा।” अंकित हो गया था, जिसे “इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीषकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें ढाला जायेगा।” पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें व्यथायत रहेंगी। उक्त शासनादेश का उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(विनोद फोनिया)  
सचिव।

संख्या: 493 / ।।—2008–03(02) / 08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को चूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2—महालेखाकार, ओमराय मोटर्स विलिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 3—वित्त विभाग (वित्त अनुभाग—4), उत्तराखण्ड शासन।
- 4—श्री एम.एल. पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5—नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6—निजी सचिव, माठ मुख्यमंत्री।
- 7—अधिकारी निवेशक, सूचना एवं सौक सम्बन्धक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8—समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9—समरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
- 10—मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- 11—निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12—गार्ड फाईल।

  
प्र० (एस०एस०टीलिया)  
अनु सचिव